प्रेस विज्ञप्ति

17 नवंबर, 2016

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, मीडिया प्रभारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं कु. सुष्मिता देव, सांसद व प्रवक्ता, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निम्नलिखित बयान जारी किया :–

1. नोटबंदी के तुगलकी निर्णय के 10 दिन बाद पूरा देश खून के आंसू रो रहा है, चारों तरफ अफरा–तफरी का आलम है, बेहाल और बेबस जनता मज़बूर है, लोग लाईनों में दम तोड़ रहे हैं और देश 'आर्थिक संकट' व 'आर्थिक अराजकता' की तरफ धकेल दिया गया है।

   यह सब केवल एक व्यक्ति की 'सनक' व 'इमेज़ बिल्डिंग' के लिए।

   आज देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं,

   जो फैसला पहले लेते हैं,

   सोचते बाद में हैं,

   और मानते कभी नहीं।

   जब गलती पकड़ी जाती है, तो सवाल पूछने वाले को 'देशद्रोही' करार दे देते हैं।

2. 10 दिन में 55 बेकसूर लोग मौत के मुंह में धकेल दिए गए। उनका क्या कसूर था? तीन हृदयविदारक घटनाएं मोदी सरकार के तुगलकी फरमान का पर्दाफाश करती हैं। रोहतक में 52 वर्षीय व्यापारी मनोज बेटी की 23 नवंबर की तय शादी के इंतजाम के पैसे न दे पाने की वजह से चल बसा। कूच बिहार (पश्चिम बंगाल) में स्कूल हेडमास्टर धरनी कांता भौमिक बेटी की शादी के लिए तीन दिन बैंक की लाईन में खड़ा हो हार्ट अटैक होकर चल बसा। अब उनकी बेटी सविता क्रियाकर्म के लिए पैसे निकलवाने बैंक लाईन में खड़ी है। सीकर, राजस्थान में 62 वर्षीय चायवाला जगदीश दो बेटियों की शादी के लिए पैसे का इंतजाम करते बैंक लाईन में ही दम तोड़ गया। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं।

   प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी को न केवल इन 55 परिवारों, पर देश के 125 करोड़ लोगों से फौरन माफी मांगनी चाहिए। इन 55 परिवारों को आर्थिक मुआवज़ा मिले व उनकी मृत्यु के कारणों की जांच कर कार्यवाही की जाए। इसकी सूची Annexure A1 संलग्न है।

3. पूरा देश नोटबंदी की बदइंतजामी से बुरी तरह बेहाल है। किसी ने सच कहा–

   'हर दिन नया फरमान,

   देश हैरान, जनता परेशान

   मोदी सरकार ने नौ दिन में 18 बार नोटबंदी के नियमों पर फैसला बदला है, जिसकी सूची Annexure A2 संलग्न है। 8 नवंबर को प्रतिव्यक्ति नोट बदलने की सीमा 4000 रुपया थी। 13 नवंबर को यह सीमा 4500 रुपया कर दी गई। आज, यानि 18 नवंबर से यह सीमा घटाकर 2000 रुपया कर दी गई। सरकार एक तरफ कहती है कि नोट

उपलब्ध हैं, तो दूसरी तरफ राशि घटा रही है। इसी प्रकार 8 नवंबर को खाते से पैसा निकालने की सीमा 20,000 रुपया, 13 नवंबर से यह सीमा 24,000 रुपया और 17 नवंबर से किसान के लिए 25,000 और व्यापारी के लिए 50,000। 8 नवंबर को एटीएम से पैसा निकालने की सीमा 2000 रुपया और 13 नवंबर को यह सीमा 2500 रुपया, जबकि एटीएम मशीन काम ही नहीं कर रही।

15 नवंबर से नोट बदलवाने पर उंगली पर स्याही लगाने का फैसला, तो 18 नवंबर को चुनाव आयोग द्वारा इस फैसले का विरोध। सरकार के दाएं हाथ को यह मालूम नहीं कि बायां हाथ क्या कर रहा है। इसे कहते हैं, ''नाच न जाने आंगन टेढ़ा''।

4. विशेषज्ञों के अनुसार 8 नवंबर के नोटबंदी फैसले से 86 प्रतिशत उपलब्ध currency बंद हो गई। 500 रु. के 1658 करोड़ नोट व 1000 रु. के 668 करोड़ नोट यानि कि कुल 2,327 करोड़ नोट बंद हो गए, जिनकी लागत लगभग 15 लाख करोड़ है। 1000 रु. के नोट 'भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राईवेट लिमिटेड' द्वारा छापे जाते हैं। दो शिफ्ट में काम करके इसकी नोट छापने की क्षमता 133 करोड़ नोट प्रतिमाह है। अगर तीन शिफ्ट में भी काम करें, तो यह हर महीने 200 करोड़ नोट छाप सकते हैं। अगर यह सरकारी कंपनी सारे 2000 रु. के नोट छापे, तो मात्र 1000 रु. के 668 करोड़ नोट की जगह 2000 रु. का नोट छापने में 3.5 महीने लगेंगे। 500 रु. का नोट सरकारी कंपनी 'सिक्योरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड' द्वारा छापा जाता है, जिसकी क्षमता 100 करोड़ नोट प्रतिमाह की है। अगर यह क्षमता रातोंरात दोगुनी भी हो जाए, तो भी 1658 करोड़, 500 रु. के नोट छापने में 8 महीने लगेंगे।

इससे साफ है कि सरकार के नए नोट उपलब्ध करवाने के सारे दावे खोखले व झूठे हैं।

5. न बैंकों में कैश है और न एटीएम में नोट। 125 करोड़ के देश में मात्र 2 लाख एटीएम हैं। वित्तमंत्री के मुताबिक 10 दिन में मात्र 22,250 एटीएम को ठीक किया गया है। इसे भी अगर सच मानें तो सारे एटीएम को ठीक करने में 110 दिन के करीब लगेंगे। ऐसे में आम जनमानस का क्या होगा?

6. नोटबंदी के पहले 5 दिनों में लोगों ने 4 लाख करोड़ रु. जमा करवाया और 71,000 करोड़ रुपया बदलवाया, तथा बैंक खातों से निकलवाया। केवल इसी बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि देश की 'खरीददारी की क्षमता' – Purchasing Power– 82 प्रतिशत कम हो गई है। स्वाभाविक है कि आर्थिक संकट के बादल सर पर मंडरा रहे हैं।

7. सबसे बड़ा मुसीबतों का पहाड़ किसान व खेत मजदूरों पर टूटा है। बगैर जाने, समझे व सोचे एक तुगलकी तरीके से सभी 'कोऑपरेटिव बैंक्स', 'ग्रामीण विकास बैंक्स', 'प्राईमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक्स' व 'कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटीज़' पर नोट बदलने या नए नोट देने पर रोक लगा दी गई है। एक झटके में समूचे खेती–बाड़ी के कारोबार की कमर तोड़ दी। नतीजा सामने है। उत्तरप्रदेश और महाराष्ट्र में न गन्ने की कटाई हो रही, न लदान और न पिराई। रबी की फसलें यानि गेहूं, जौ, चना , आलू इत्यादि के लिए न बीज का पैसा है, न खाद का और न ही मजदूर को देने का। मोदी जी ने तो खुद के

कृषि मंत्रालय की गुहार भी नकार दी, जो चाहते थे कि किसान पुराने नोटों से बीज और खाद खरीद सके। समूची कृषि व्यवस्था पंगु है।

8. यही हाल छोटे और मध्यम उद्योगों का भी है। एक उदाहरण, तिरुपुर, तमिलनाडु का, जहां प्रतिवर्ष 32000 करोड़ के knit wear का उत्पादन होता है। यहां पर उद्योगों में 5 लाख मजदूर हैं, जिनमें से अधिकतर को तनख्वाह नकदी में दी जाती है। अगर एक फैक्ट्री में 1000 कर्मचारी हैं, जिन्हें प्रति सप्ताह 2000 रु. का भुगतान होता है, तो 20 लाख रु. की राशि चाहिए। परंतु मोदी सरकार ने यह सीमा 50,000 रु. रख दी है। ऐसे में तिरुपुर (तमिलनाडु) हो या सूरत, लुधियाना, पानीपत या देश के अन्य औद्योगिक केंद्र। नतीजा होगा, मजदूर की नौकरी पर हमला। यही हाल को–ऑपरेटिव डेयरी सोसायटीज़ का है, जहां दूध पैदा करने वाले किसान को नकद भुगतान किया जाता है। यह दिखाता है कि पूरे देश में नकदी के भुगतान से चलने वाली अर्थव्यवस्था पर कितनी गहरी मार पड़ी है।

9. यही नहीं विदेशी निवेशकों का विश्वास भी टूटता जा रहा है। नोटबंदी के बाद पहले 5 दिनों में ही विदेशी निवेशक एक बिलियन अमेरिकी डॉलर या लगभग 6500 करोड़ रुपया देश से बाहर ले गए। इन सबके बावजूद मुसीबत बताने वालों व सवाल पूछने वालों को देशद्रोही कहा जा रहा है। समय आ गया है कि देश के लोग निर्णय करें कि असली देशद्रोही कौन है।